VIDYA BHAWAN BALIKA VIDYA PITH

शक्ति उत्थान आश्रम लखीसराय बिहार

Class 12 commerce Sub. ECO(b) Date 12.04.2021

Teacher name – Ajay Kumar Sharma

INDIAN ECONOMY ON THE EVE OF INDEPENDENCE

Question 1:

What was the focus of the economic policies pursued by the colonial government in India? What were the impacts of these policies?

ANSWER:

The main focus of the economic policies pursued by the colonial government was to make India a mere supplier of Britain's own flourishing industrial base. The policies were concerned mainly with the fortification and advancement for their home country. The interests of the Indian economy were completely ignored. Such policies brought structural changes in the Indian economy by transforming it to a supplier of raw materials and consumer of finished products from Britain. The impacts of these policies are discussed as follows in detail;

i. *Low Economic Development*

Throughout the British rule, Indian economy experienced very low level of economic development. As per some researches, Indian economy grew at even less than two percent during 1900-50. The reason for such a low level of development was that the British government was more concerned with the promotion of economic interests of their home country. Consequently, the colonial rule transformed India's agriculture sector to a mere supplier of raw materials for the British industries. This not only affected the production of the agricultural sector but also ruined the small manufacturing units like handicrafts and cotton industries. These manufacturing units faced a stiff competition from the British machine made textiles and handlooms.

ii. *Backwardness of Indian Agriculture*

Under the colonial rule, India was basically an agrarian economy employing nearly 85% of its population. Nevertheless, the growth of the agriculture sector was meager. This was due to the prevalence of various systems of Land Settlement, particularly *Zamindari* system. Under this system, the zamindars (owners of land) were required to pay very high revenue (*lagaan*) to the British government, which they used to collect from the peasants (landless labourers, who were actually cultivating). The zamindars were mainly concerned with extracting high revenues from the peasants but never took any steps to improve the productivity of the land. Moreover, in order to feed British industries with cheap raw materials, the Indian peasants were forced to grow cash crops (such as, indigo, cotton, etc.) instead of food crops (such as, rice and wheat). This commercialisation of agriculture not only increased the burden of high revenues on the poor peasants but also led India to face shortage of food grains. Therefore, Indian agriculture remained backward and primitive.

iii. *Deindustrialisation of Indian Economy*

India failed to develop a sound and strong industrial base during the colonial rule. The status of industrial sector during the British rule can be well defined by the term ‘systematic deindustrialisation’. The cause of deindustrialisation can be attributed to the downfall of India’s handicraft industry and the cause of bleak growth of modern industry was the lack of investment. On one hand, the British government imposed heavy tariffs on the export of Indian handicraft products and on the other hand, allowed free exports of Indian raw materials to Britain and free imports of British products to India. As a result of the heavy tariffs, the Indian exports became costlier and its demand in the international market fell drastically that led to the collapse of Indian handicrafts industries. Simultaneously, the demand for the handicrafts products also fell in the domestic markets due to stiff competition from the machine made textiles of Britain. As a result, the domestic industries lacked investment and growth initiatives.

iv. *Regression in Foreign Trade*

During the colonial rule, the British government owned the monopoly power over India’s foreign trade. The British government used the trade policy according to the interests of their home country. The exports and imports transactions were restricted only to India and Britain. On one hand, the exports from India provided the cheap raw materials to the British industries and on the other hand, India's imports from Britain provided a virgin market for Britain’s products. In either ways, British industries were benefitted. Moreover, the surplus generated from t foreign trade was not invested in the Indian economy; instead it was used in administrative and war purposes by Britain to spread their colonial power.

प्रश्न 1:

भारत में औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों का क्या ध्यान था? इन नीतियों के प्रभाव क्या थे?

उत्तर:

औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों का मुख्य फोकस भारत को ब्रिटेन के अपने समृद्ध औद्योगिक आधार का एक मात्र आपूर्तिकर्ता बनाना था। नीतियां मुख्य रूप से अपने देश के लिए किलेबंदी और उन्नति से संबंधित थीं। भारतीय अर्थव्यवस्था के हितों की पूरी तरह अनदेखी की गई। ऐसी नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में कच्चे माल और ब्रिटेन से तैयार उत्पादों के उपभोक्ता के रूप में परिवर्तित करके संरचनात्मक परिवर्तन लाए। इन नीतियों के प्रभावों पर विस्तार से चर्चा की गई है;

मैं। कम आर्थिक विकास

ब्रिटिश शासन के दौरान, भारतीय अर्थव्यवस्था ने आर्थिक विकास के निम्न स्तर का अनुभव किया। कुछ शोधों के अनुसार, भारतीय अर्थव्यवस्था 1900-50 के दौरान दो प्रतिशत से भी कम पर बढ़ी। विकास के इतने निम्न स्तर का कारण यह था कि ब्रिटिश सरकार

अपने गृह देश के आर्थिक हितों को बढ़ावा देने से अधिक चिंतित थी। नतीजतन, औपनिवेशिक शासन ने भारत के कृषि क्षेत्र को ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल के एक मात्र आपूर्तिकर्ता में बदल दिया। इसने न केवल कृषि क्षेत्र के उत्पादन को प्रभावित किया बल्कि हस्तशिल्प और कपास उद्योगों जैसी छोटी विनिर्माण इकाइयों को भी बर्बाद कर दिया। इन निर्माण इकाइयों को ब्रिटिश मशीन द्वारा निर्मित वस्त्र और हथकरघा से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा।

ii। भारतीय कृषि का पिछड़ापन

औपनिवेशिक शासन के तहत, भारत मूल रूप से एक कृषि अर्थव्यवस्था था जो अपनी आबादी का लगभग 85% हिस्सा था। फिर भी, कृषि क्षेत्र की वृद्धि अल्प थी। यह भूमि निपटान की विभिन्न प्रणालियों, विशेष रूप से जमींदारी प्रणाली की व्यापकता के कारण था। इस प्रणाली के तहत, जमींदारों (भूमि के मालिकों) को ब्रिटिश सरकार को बहुत अधिक राजस्व (लगान) का भुगतान करना पड़ता था, जिसे वे किसानों (भूमिहीन मजदूरों, जो वास्तव में खेती कर रहे थे) से एकत्र करते थे। ज़मींदार मुख्य रूप से किसानों से उच्च राजस्व निकालने के लिए चिंतित थे, लेकिन उन्होंने कभी भी भूमि की उत्पादकता में सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाया। इसके अलावा, सस्ते कच्चे माल के साथ ब्रिटिश उद्योगों को खिलाने के लिए, भारतीय किसानों को खाद्य फसलों (जैसे, चावल और गेहूं) के बजाय नकदी फसलों (जैसे, इंडिगो, कपास, आदि) को उगाने के लिए मजबूर किया गया था। कृषि के इस व्यावसायीकरण ने न केवल गरीब किसानों पर उच्च राजस्व का बोझ बढ़ाया, बल्कि भारत को खाद्यान्न की कमी का सामना करना पड़ा। इसलिए, भारतीय कृषि पिछड़ी और आदिम रही।

iii। भारतीय अर्थव्यवस्था का औद्योगीकरण

भारत औपनिवेशिक शासन के दौरान एक मजबूत और मजबूत औद्योगिक आधार विकसित करने में विफल रहा। ब्रिटिश शासन के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति को de व्यवस्थित विचलन 'के रूप में अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है। भारत के हस्तकला उद्योग के पतन के लिए विस्थापन का कारण बन सकता है और आधुनिक उद्योग की धूमिल वृद्धि का कारण निवेश की कमी है। एक तरफ, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों के निर्यात पर भारी शुल्क लगाया और दूसरी तरफ, ब्रिटेन को भारतीय कच्चे माल के मुफ्त निर्यात और ब्रिटिश उत्पादों के भारत में मुफ्त आयात की अनुमति दी। भारी शुल्क के परिणामस्वरूप, भारतीय निर्यात महंगा हो गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग में भारी गिरावट आई जिसके कारण भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ। इसके साथ ही, ब्रिटेन के मशीन से बने वस्त्रों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण घरेलू उत्पादों में हस्तशिल्प उत्पादों की मांग भी गिर गई। परिणामस्वरूप, घरेलू उद्योगों में निवेश और विकास की पहल की कमी थी।

iv। विदेश व्यापार में प्रतिगमन

औपनिवेशिक शासन के दौरान, ब्रिटिश सरकार के पास भारत के विदेशी व्यापार पर एकाधिकार शक्ति थी। ब्रिटिश सरकार ने अपने गृह देश के हितों के अनुसार व्यापार नीति का उपयोग किया। निर्यात और आयात लेनदेन केवल भारत और ब्रिटेन तक ही सीमित थे। एक तरफ, भारत से निर्यात ने ब्रिटिश उद्योगों को सस्ते कच्चे माल प्रदान किए और दूसरी ओर, ब्रिटेन से भारत के आयात ने ब्रिटेन के

उत्पादों के लिए एक कुंवारी बाजार प्रदान किया। किसी भी तरह से, ब्रिटिश उद्योगों को लाभ हुआ। इसके अलावा, टी विदेशी व्यापार से उत्पन्न अधिशेष भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश नहीं किया गया था; इसके बजाय ब्रिटेन द्वारा प्रशासनिक और युद्ध के उद्देश्यों में इसका उपयोग अपनी औपनिवेशिक शक्ति को फैलाने के लिए किया गया था।